

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 16 FEBRUARY 2022 TO 22 FEBRUARY 2022

Inside News

Page 3

एलआईसी के पास 'लावरिस' पड़े हैं 21500 करोड़ रुपये



चीन की टेलिकॉम कंपनी हुवावे पर इनकम टैक्स का छापा, टैक्स चोरी का आरोप

Page 4



■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 24 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

मजबूत और लोचदार, फिर भी सँझे योग्य प्रोटीन आधारित बायोप्लास्टिक्स

Page 5



editorial!

बेकाबू ना हो महंगाई

आरबीआई के पास पैसा जमा करने पर बैंकों को मिलने वाली ब्याज दर यानी रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीसदी पर रहने दिया गया। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में 0.15-0.40 फीसदी तक बढ़ोतरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रिजर्व बैंक के दरों में बदलाव ना करने की वजह यह है कि वह इकॉनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट देना चाहता है। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार दसवां मौका है, जब दरें जस की तस रखी गई। आखिरी बार 22 मई 2020 को पॉलिसी रेट में बदलाव हुआ था। तब ब्याज दरें घटाई गई थीं। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देता है, उस रेपो रेट को 4 फीसदी पर बनाए रखा गया। आरबीआई के पास पैसा जमा करने पर बैंकों को मिलने वाली ब्याज दर यानी रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीसदी पर रहने दिया गया। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में 0.15-0.40 फीसदी तक बढ़ोतरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रिजर्व बैंक के दरों में बदलाव ना करने की वजह यह है कि वह इकॉनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट देना चाहता है। इससे पहले 2014 में कच्चे तेल के दाम 95 डॉलर पर गए थे।

महंगा होगा डीजल-पेट्रोल

क्रूड ऑयल 8 साल के रिकॉर्ड हाई पर

5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम

नई दिल्ली! एजेंसी

उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। विधान सभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं इसके बाद पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम 8 साल के हाई लेवल पर जा पहुंचे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 95 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले 2014 में कच्चे तेल के दाम 95 डॉलर पर गए थे।

100 डॉलर के पार जा सकता है कच्चा तेल

एक दिसंबर 2021 को कच्चे तेल का दाम 69 डॉलर प्रति बैरल था, जो अब 95 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। यानी ढाई महीने के भीतर कच्चे तेल के दामों में 37% की तेजी आ चुकी है। एक्सपटर्स के मुताबिक, कच्चा तेल 1 डॉलर प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल-डीजल के दाम औसतन 55-60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाते हैं। ऐसे में यदि क्रूड 100 डॉलर पर पहुंचे तो पेट्रोल-डीजल के दाम 10 रुपए तक बढ़ सकते हैं।

मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं

टेक्सास की ऑयल कंपनी पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज के स्कॉट शोफील्ड ने कहा- अगर पुतिन हमला करते हैं, तो कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, लेकिन अगर बाइडेन ईरान पर से प्रतिबंध हटाते हैं, तो इनमें 10 डॉलर की गिरावट होगी। फिलहाल मार्केट में जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं है, इस वजह से यह तो तय है कि

कीमतें 100 डॉलर के पार जाएंगी।

चुनाव आते ही लग जाता है पेट्रोल-



डीजल की कीमतों पर ब्रेक

एक्सपटर्स के अनुसार सरकार भले ही पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करने में अपनी भूमिका से इनकार करती हो, लेकिन बैते सालों में ऐसा देखा गया है कि चुनाव के दौरान सरकार जनता को खुश करने के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाती है। पिछले सालों का ट्रैंड बता रहा है कि चुनावी मौसम में जनता को पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों से राहत मिली है।

15 रुपए तक बढ़ सकते हैं

पेट्रोल-डीजल के दाम

IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटी एंड करेंसी) अनुज गुप्ता कहते हैं कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। वहीं तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन तब जब लेकर अब तक कच्चा तेल 15 डॉलर

प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, आगे भी इसमें

के दाम नहीं बढ़े हैं। रुझान बताते हैं कि पिछले करीब साढ़े तीन महीने से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में काफी तेजी आई है।

पेट्रोल-डीजल की कीमत कर्से निर्धारित होती है?

जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदल जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। अभी ऑयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल-डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं।

भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत कच्चा तेल करता है आयात

हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। इसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल-डीजल महंगे होने लगते हैं। कच्चा तेल बैरल में आता है। एक बैरल, यानी 159 लीटर कच्चा तेल होता है।

ऑल टाइम हाई पर जेट फ्लाइट के दाम, दो महीने के अंदर चौथी बार बढ़ी कीमतें

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच बुधवार को विमान ईंधन की कीमतों में 5.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद देश में जेट फ्लाइट के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दो महीनों के भीतर देश में चौथी बार जेट फ्लाइट की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जेट फ्लाइट की कीमतों में 4,481.63 रुपए प्रति किलोलीटर या 5.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अब 90,519.79 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई थीं। जिसके बाद अब जाकर जेट फ्लाइट की कीमतों में बढ़ोतरी की कीमतें अगस्त 2008 की तुलना में काफी कम हैं।

नासकॉम की रिपोर्ट

महामारी में आईटी कंपनियों की कमाई एक दशक में सबसे ज्यादा

एजेंसी, मुंबई।

रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी क्षेत्र में नौकरी छोड़ने की दर उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। उद्योग निकाय के उपाध्यक्ष कृष्णन रामानुजन ने कहा कि अगर दिसंबर तिमाही में शीर्ष-10 आईटी कंपनियों के आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है तो भी यह स्थिर है। महामारी के दौरान आईटी कंपनियों की कमाई में बंपर तेजी देखने को मिली है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कमाई 2021-22 में 15.5 फीसदी बढ़ोतारी के साथ 227 अरब डॉलर पहुंच सकती है। यह वृद्धि पिछले एक दशक के किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। आईटी उद्योग की संस्था नासकॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष ने कहा कि देश की आईटी कंपनियों के लिए 2021-22 शानदार रहा है। कोरोना संकट के दौरान आईटी सेवाओं की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। इससे इन

कंपनियों की कमाई भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 15.5 फीसदी की वृद्धि पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में हुई वृद्धि में सबसे अधिक है। उद्योग निकाय के अनुसार, 2020-21 में आईटी क्षेत्र की आय 2.3 फीसदी बढ़कर 194 अरब डॉलर रही थी।

4.5 लाख नई नौकरियां

नासकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी उद्योग ने कुल प्रत्यक्ष कर्मचारियों की संख्या को 50 लाख तक पहुंचाने के लिए 4.5 लाख नई नौकरियां दी। नए कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या 44 फीसदी रही, जिससे उनकी कुल संख्या बढ़कर 18 लाख पहुंच गई है।

निर्यात से आय 17 फीसदी बढ़ी

भारतीय आईटी कंपनियों की निर्यात से आय 17.2 फीसदी बढ़कर 178 अरब डॉलर हो गई है, जबकि घरेलू आय 10 फीसदी की बढ़ोतारी के साथ 49 अरब डॉलर पहुंच गई है।

घोष ने कहा कि आईटी क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं की हिस्पेदारी 25 फीसदी बढ़कर 13 अरब डॉलर हो गई है। देश के पास भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत कार्यबल है।

नौकरी छोड़ने की दर उच्चतम स्तर पर

रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी क्षेत्र में नौकरी छोड़ने की दर उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। उद्योग निकाय के उपाध्यक्ष कृष्णन रामानुजन ने कहा कि अगर दिसंबर तिमाही में शीर्ष-10 आईटी कंपनियों के आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है तो भी यह स्थिर है। उम्मीद है कि आईटी क्षेत्र में हम इस समस्या के चरम को छू चुके हैं। आगे स्थिति बेहार होने की उम्मीद है। नासकॉम के अनुसार, हाल की तिमाहियों में दुनियाभार में डिजिटलीकरण की मांग बढ़ने से कई कंपनियों ने 20 फीसदी से अधिक कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की सूचना दी है।

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

वीडियो कॉलिंग से खरीद सकेंगे बीमा पॉलिसी

नई दिल्ली। एजेंसी

वर्तमान समय में बैंकों के अलावा शेयर ब्रोकिंग कंपनियां वीडियो कॉलिंग से केराइसी की सुविधा दे रही हैं। बैंक कुछ खास सेवाओं के लिए इसे अपना रहे हैं। बीमा क्षेत्र की इस पहल पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मुख्य व्यवसाय अधिकारी (डिजिटल) विवेक नारायणन का कहना है कि महामारी ने स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता और सही कवरेज चुनने की चिंता को जन्म दिया है। हमने वीडियो कॉलिंग के साथ प्रयोग किया क्योंकि इसने हमारे सलाहकारों को हमारे ग्राहकों और उनके परिवार के साथ अधिक घनिष्ठ और प्रभावी ढंग से जुड़ने की सुविधा दी। नतीजतन, तीन गुना अधिक इच्छुक ग्राहक ऑफिडों कॉल की तुलना में वीडियो कॉल पर बीमाकर्ता के साथ एक उपयुक्त स्वास्थ्य पॉलिसी हासिल करने के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना संकट के बाद बैंक, शेयर ब्रोकिंग कंपनियों के अलावा बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों तक अधिक सुविधाजनक पहुंच के लिए अब वीडियो कॉल पर सेवाओं देने की शुरुआत कर दी है। इसे ग्राहक ज्यादा भरोसेमंद और सुविधाजनक मानकर इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारत की निजी क्षेत्र की प्रमुख सामान्य बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले अपने सभी ग्राहकों के लिए एक वीडियो कॉलिंग सुविधा शुरू की है। यह पहल ग्राहक को केवल तीन आसान चरणों में अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से तत्काल वीडियो कॉल करने या उसका समय निर्धारित करने की सुविधा प्रदान की है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस तरह के समाधान की पेशकश करने वाली भारत की पहली बीमा कंपनी है। कंपनी का कहना है कि इसके परिणाम शानदार रहे हैं और हमारा मानना है कि यह आगे चलकर ग्राहकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा खरीदने के तरीके में बदलाव का प्रतीक है। बीमाकर्ता पहले ही वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे भारत में हजारों ग्राहकों से जुड़ चुका है। यह पहल ग्राहकों को यह चुनने में मदद करने के लिए एक व्यक्तिगत स्पर्श देती है कि उनकी जरूरतों को सबसे ज्यादा पूरा करता है।

बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्य अर्थशास्त्री पद के लिए आवेदन मांगे

नई दिल्ली। एजेंसी

बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने मुख्य अर्थशास्त्री पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर तीन साल के लिए होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बुधवार को कहा कि आवेदनकर्ता के पास एमए अर्थशास्त्र की प्रथम श्रेणी या एम इकनॉमेट्रिक्स में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए।

बैंक की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया है कि इस पद के लिए वांछित योग्यता पीएच. डी अर्थशास्त्र या इकनॉमेट्रिक्स है।

इसके अलावा आवेदन करने वाले अभ्यार्थी के पास किसी वित्तीय संस्थान/बैंक/रेटिंग एजेंसी/मीडिया कंपनी, शोध संगठनों में अधिकारी के रूप में काम करने का सात साल का अनुभव होना चाहिए।

अभ्यार्थी की आयु 45 से 55 साल होनी चाहिए। ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी, 2022 है।

सेबी ने बदला अपना फैसला सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरपर्सन और एमडी का पद अलग करना जरूरी नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

पूँजी बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक (एमडी)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद अलग-अलग करने के अपने फैसले को बदल दिया है। इसके तहत अब चेयरपर्सन और एमडी/सीईओ के पदों को अलग करने के अपने बोर्ड के बाद कहा कि उसके बोर्ड ने यह फैसला किया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए चेयरपर्सन और एमडी/सीईओ के पदों को अलग-अलग करने का सुझाव दिया था। नियामक ने मई, 2018 में इन पदों को अलग करने के नियम पेश किए थे।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अगली पीढ़ी के सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। अब अपनी जरूरत के हिसाब से चेयरपर्सन और एमडी/सीईओ के इस

पद अलग-अलग या एक साथ रख सकती हैं। दरअसल, जून, 2017 में सेबी कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर उदय कोटक की अगुवाई में एक समिति बनाई थी। समिति ने चेयरपर्सन और एमडी/सीईओ के पदों को अलग-अलग करने का सुझाव दिया था। नियामक ने इन पदों को अलग-अलग करने के नियम पेश किए थे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अगली पीढ़ी के सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कदमों का बाजार पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सेबी के निदेशक मंडल को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि नियामक की ओर से उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं। हालांकि, अभी नियमों के अनुपालन बोझ को कम करने, बाजार मध्यस्थता की लागत के अलावा निवेशकों के हितों के अधिक सुरक्षित करने की दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूती देने और ग्रीन बॉन्ड बाजार के विकास की दिशा में भी प्रयास करने को कहा है।

आर्थिक पायदान : देश का नियात 25.28 फीसदी बढ़ा, व्यापार घाटे में भी इजाफा, इन क्षेत्रों ने दिखाया दम

नई दिल्ली। एजेंसी

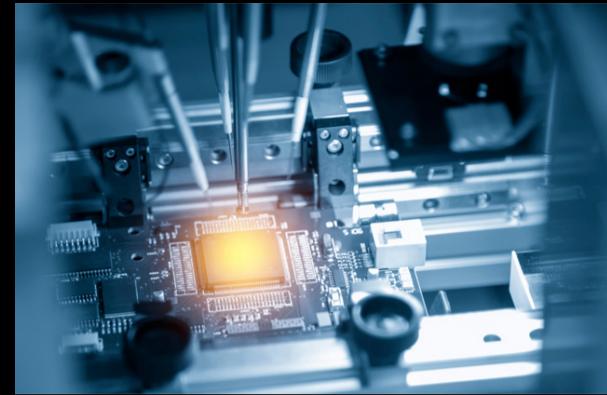
इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और रस्ते एवं आभूषण क्षेत्र के दमदार प्रदर्शन से देश का नियात इस साल जनवरी में 25.28 फीसदी बढ़कर 335.88 अरब डॉलर रहा। आलोच्य अवधि में आयात 62.65 फीसदी वृद्धि के साथ 495.75 अरब डॉलर और व्यापार घाटा 75.87 अरब डॉलर से बढ़कर 159.87 अरब डॉलर पहुंच गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने कहा कि जनवरी में

आयात बढ़कर 51.93 अरब डॉलर पहुंचना चिंता की बात है।

आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में पेट्रोलियम उत्पादों का नियात 95.23 फीसदी बढ़ गया। इंजीनियरिंग उत्पादों और रस्ते एवं आभूषण में क्रमशः 24.11 फीसदी और 13.64 फीसदी तेजी रही। सेवा नियात 40.52 फीसदी कम होकर 2.4 अरब डॉलर रहा। हालांकि, सेवों का आयात 54.95 फीसदी बढ़कर 26.91 अरब डॉलर पहुंच गया। हालांकि, औषधि नियात 1.15 फीसदी घटकर 2.05 अरब डॉलर

रहा।

इस साल जनवरी में कच्चे तेल का आयात 26.9 फीसदी बढ़कर 11.96 अरब डॉलर पहुंच गया। सेवाओों का आयात 60.32 फीसदी बढ़कर 15.83 अरब डॉलर रहा। हालांकि, सेवों का आयात 40.52 फीसदी कम होकर 2.4 अरब डॉलर रहा। अप्रैल-जनवरी में सेवाओं का आयात 27.69 फीसदी बढ़ोतारी के साथ 121.16 अरब डॉलर रहा।



मुंबई। एजेंसी

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की

तरफ से की गई पहले को उद्योग जगत से मिली 'शानदार' प्रतिक्रिया का मांगलवार को स्वागत किया। वैष्णव ने आईटी उद्योग के संगठन नैसकॉम के रणनीतिक समीक्षा संवाददाता

सम्मेलन में उद्योग जगत से अपनी कोशिशें और बढ़ाने का आहारन भी किया। वैष्णव ने कहा, "मुझे बेहद खुशी है कि बहुत कम समय में सेमीकंडक्टर विनिर्माण से जुड़े भारीदारों से शानदार प्रतिक्रिया देखने को मिली है।" वैष्णव का सेमीकंडक्टर अभियान को शानदार प्रतिक्रिया मिलने का यह बयान वेदांता का फॉकसकॉम के साथ सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए हुए करार के एक

दिन बाद आया है। इसके पहले टाटा समूह भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण में उत्तरने को लेकर दिलचस्पी दिखा चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 15 दिसंबर, 2021 को घेरू स्तर पर सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,600 करोड़ रुपये लागत वाली योजना को मंजूरी दी थी। इससे सेमीकंडक्टर की किल्लत को दूर करने और देश में इसका उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप के डिजाइन एवं विनिर्माण दोनों ही क्षेत्रों में उद्योग जगत ने खासा उत्साह दिखाया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, "ये सभी रोजगार के नए अवसर होंगे। उद्योग जगत से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी कोशिशों को और तेज करें। आप नए विचार एवं सुझावों के साथ सामने आएं।"

उन्होंने कहा कि सरकार को इस नए विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग जगत से मिलने वाले सुझावों का इंतजार है। इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में आईटी क्षेत्र में 4.5 लाख नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए उद्योग का आभार भी जताया। इस तरह आईटी क्षेत्र में मिलने वाले प्रत्यक्ष रोजगार की संख्या 50 लाख हो चुकी है।

चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह में रत्न एवं आभूषण निर्यात 6.5 प्रतिशत बढ़कर 32.37 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली। एजेंसी

चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह (अप्रैल-जनवरी) के दौरान देश का रत्न एवं आभूषण निर्यात 6.5 प्रतिशत बढ़कर 32.37 अरब डॉलर पर पहुंच गया। उद्योग संगठन रत्न एवं आभूषण निर्यात संबद्धन परिषद (जीजेर्हीपीसी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में रत्न एवं आभूषण निर्यात 30.40 अरब डॉलर रहा था। जीजेर्हीपीसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले दस माह में शीर्ष 10 निर्यात वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात (41.50 प्रतिशत), बेल्जियम (15.81 प्रतिशत), जापान (12.20 प्रतिशत) और हांगकांग (3.06 प्रतिशत) शामिल हैं।



उद्योग संगठन ने कहा कि यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के क्रियान्वयन के बाद सोने और सोना जड़ित आभूषणों के निर्यात को और

आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

परिषद ने सरकार से कहा है कि वह भारत से सोने, चांदी और प्लैटिनम के आभूषणों के निर्यात पर संयुक्त अरब अमीरात में पांच प्रतिशत के आयात शुल्क को समाप्त करने की बात उठाए। जीजेर्हीपीसी ने कहा, "भारतीय रत्न और आभूषण निर्यात क्षेत्र ने अबतक 2.4 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ कोरोना वायरस महामारी के बाद तेजी से सुधार दिखाया है। इसमें अप्रैल, 2021 से जनवरी, 2022 के दौरान 12.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 के दौरान 2.14 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था।" इसके अलावा अप्रैल-जनवरी, 2022 के दौरान सोने के आभूषणों का निर्यात 24.24 प्रतिशत घटकर 7.68 अरब डॉलर रहा और सामान्य सोने के आभूषणों का निर्यात भी लगभग 56 प्रतिशत गिरकर 3.2 अरब डॉलर रहा।

उद्योग संगठन ने कहा कि यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के क्रियान्वयन के बाद सोने और सोना जड़ित आभूषणों के निर्यात को और

अनुसार, इसमें बिना दावे वाली राशि पर परिषद्र में इसके बारे में प्रक्रियाओं का व्योरा दिया गया है। इन प्रक्रियाओं में बिना दावे वाली राशि का भुगतान, पॉलिसीधारकों को सूचना, लेखा और निवेश आय का इस्तेमाल आदि शामिल है।

इंदौर की सॉफ्ट पावर भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित कर रही है

इंदौर। आईटी नेटवर्क

इंदौर तेजी से देश के नए आईटी हब के रूप में उभर रहा है। इंदौर को अपनी सूची में जोड़ने के लिए शहर अब कुछ बड़े आईटी ब्रांडों का गंतव्य है, जबकि अन्य पाइपलाइन में हैं। इस बीच, शहर की अपनी सॉफ्टवेयर कंपनियों वहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और सॉफ्टवेयर निर्यात में बड़े नामों के मानकों का मिलान कर रही हैं, इस प्रकार शहर और मध्य प्रदेश राज्य को ख्याति दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर योगदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

सेरोसॉफ्ट सॉल्यूशंस प्रा। लिमिटेड इंदौर का एक ऐसा ब्रांड है जो भारत में सबसे तेजी से बढ़ती शैक्षिक सॉफ्टवेयर और समाधान कंपनियों में से एक के रूप में उभरा है। आईटी स्टार्टअप होने से लेकर एडटेक स्पेस में उन्हें बनने में सेरोसॉफ्ट ने एक लंबा

सफर तय किया है। डेलॉइट फास्ट 50, एशिया पैसिफिक (एपीएसी) 2018, 2018 रेड हेरिंग, एसआईएस श्रेणी में एडटेक कूल टूल अवार्ड्स 2019 फाइनलिस्ट आदि जैसे गर्व से गर्व करने के लिए सेरोसॉफ्ट ने लगभग 20 देशों के संस्थानों को सेवा दी है। उन्होंने अपने पूर्ण डिजिटल परिवर्तन के लिए सेरोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है।

लेसोथो- एक अप्रौक्ती के देश के एक प्रतिनिधिमंडल ने अवसर का पता लगाने के लिए मंगलवार को इंदौर का दौरा किया, जो उनके शैक्षणिक संस्थान को उनकी जरूरतों के लिए विश्व स्तर का समाधान करने में मदद करेगा, साथ ही वे शहर की स्वच्छता से प्रभावित हुए और उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि इंदौर ने लगातार 5 बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का नंबर एक टैग हासिल किया है। इंदौर ने वास्तव में एक बेहतर आईटी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक लंबा सफर तय किया है, हालांकि अभी बहुत कुछ हासिल करना है।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण पहल को उद्योग जगत से मिली शानदार प्रतिक्रिया: वैष्णव

दिन बाद आया है। इसके पहले टाटा समूह भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण में उत्तरने को लेकर दिलचस्पी दिखा चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 15 दिसंबर, 2021 को घेरू स्तर पर सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,600 करोड़ रुपये लागत वाली योजना को मंजूरी दी थी। इससे सेमीकंडक्टर की किल्लत को दूर करने और देश में इसका उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप के डिजाइन एवं विनिर्माण दोनों ही क्षेत्रों में उद्योग जगत ने खासा उत्साह दिखाया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, "ये सभी रोजगार के नए अवसर होंगे। उद्योग जगत से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी कोशिशों को और तेज करें। आप नए विचार एवं सुझावों के साथ सामने आएं।"

एलआईसी के पास 'लावारिस' पड़े हैं 21500 करोड़ रुपये खुद कंपनी के ही दस्तावेजों से हुआ खुलासा!

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास सिस्टंबर, 2021 तक 21,539 करोड़ रुपये का ऐसा कोष था, जिसके 'दोवेदार' नहीं थे। एलआईसी की तरफ से भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) दस्तावेज से यह जानकारी मिली है। दस्तावेजों के अनुसार, इसमें बिना दावे वाली राशि पर ब्याज भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मार्च, 2021 तक बिना दावे वाला कोष 18,495 करोड़ रुपये और मार्च, 2020 के अंत तक 16,052.65 करोड़ रुपये था। वहीं मार्च, 2019

के अंत तक यह राशि 13,843.70 करोड़ रुपये थी। प्रत्येक बीमा कंपनी को 1,000 रुपये या उससे अधिक की बिना दावे वाली राशि का व्योरा अपनी वेबसाइट पर डालना होता है। वेबसाइट पर पॉलिसीधारकों या लाभार्थियों को बिना दावे वाली राशि के सत्यापन की सुविधा भी प्रदान करने की ज़रूरत होती है। दस्तावेजों में कहा गया है कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के बिना दावे वाली राशि पर परिषद्र में इसके बारे में प्रक्रियाओं का व्योरा दिया गया है। इन प्रक्रियाओं में बिना दावे वाली राशि का भुगतान, पॉलिसीधारकों को सूचना, लेखा और निवेश आय का इस्तेमाल आदि शामिल है।

अब बाइक पर बच्चों को भी लगाना होगा हेलमेट, स्पीड भी रहेगी कम, जानिए क्या हैं नए नियम और कब से होंगे लागू

नई दिल्ली। एजेंसी

ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अब बाइक पर चलने वाले छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार अगर 4 साल से छोटा कोई बच्चा दो-पहिया वाहन पर सवार है तो उसे क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी है। इतना ही नहीं, कुछ और भी नियम लागू किए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बच्चों को बिना किसी

सुरक्षा उपायों के ही लोग मोटरसाइकिल या स्कूटर पर लेकर धूमते हैं। सोशल मीडिया पर तो ऐसी भी तस्वीरें आती रहती हैं, जिसमें एक ही बाइक पर 5-10 बच्चे तक बैठाए होते हैं, लेकिन ये उनकी सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने नए नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या हैं नए नियम में।

क्रैश हेलमेट है जरूरी

4 साल से छोटे बच्चों को दो-पहिया

वाहन की सवारी के दौरान क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी है। क्रैश हेलमेट वह हेलमेट होते हैं, जिनमें सिर पूरी तरह से कवर होता है, ना कि सिर्फ टोपी की तरह पहना जाने वाला हेलमेट। ये नए नियम आने के बाद भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां उप्र के हिसाब से सुरक्षा के उपाय हैं और बच्चों के लिए भी सुरक्षा के उपाय हैं।

सेफ्टी हार्नेस भी है जरूरी

अगर बच्चा बाइक चलाने वाले शख्स

के पीछे बैठा है तो उसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने जरूरी हैं। इसके तहत बच्चे के लिए सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए, ताकि बच्चा पीछे से गिरे नहीं। एक सेफ्टी हार्नेस बच्चों को राइडर से बांधे रखता है और वह 30 किलो तक का वजन उठा सकता है। तो अगर आप भी अपने छोटे बच्चे को बाइक पर लेकर कहीं निकलें तो नियमों का ध्यान रखें।

स्पीड पर लगाई लगाई

यह भी कहा गया है कि जिस दो-

पहिया वाहन पर 4 साल से छोटा बच्चा बैठा हो, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीड तेज होगी तो बच्चे को हेलमेट होने के बावजूद गिरने पर चोट लग सकती है। इतना ही नहीं, सेफ्टी हार्नेस के बावजूद छोटा बच्चा तेज स्पीड वाली बाइक के गिरने से गंभीर रूप से घायल हो सकता है, इसलिए स्पीड पर भी लगाम लगाई गई है।

चीन से आयात आधा होने पर जीडीपी में 20 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी

मुंबई। एजेंसी

भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का फायदा उठकर अगर चीन से होने वाले आयात पर अपनी निर्भरता को 50 प्रतिशत तक कम करने में सफल रहता है, तो उसके सकल धरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 20 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। एस्याओआई रिसर्च की मंगलवार को जारी रिपोर्ट 'इकोरेप' में यह अनुमान जताया गया। इसके मुताबिक, चीन के साथ अपने व्यापार घटे को भारत वर्ष 2020-21 में कम करने में सफल रहा लेकिन भारत के कुल वस्तुओं के आयात में चीन की हिस्सेदारी 16.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2020-21 में चीन से किए गए 65 अरब डॉलर के आयात में करीब 39.5 अरब डॉलर मूल्य जिससे एवं उत्पादों का रहा था। भारत ने कपड़ा, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, फार्मा एवं रसायन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि "अगर पीएलआई योजनाओं की वजह से हम चीन से होने वाले आयात को 20 प्रतिशत तक भी कम कर पाने में सफल रहते हैं, तो हम अपनी जीडीपी में आठ अरब डॉलर की वृद्धि कर लेंगे। वहीं चीन पर आयात निर्भरता में 50 फीसदी कमी होने पर हमारी जीडीपी में 20 अरब डॉलर की वृद्धि हो जाएगी।" चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में भारत ने चीन से 68 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों का आयात किया है।



उसका संचालन पूरी तरह कानून के पालन के साथ चल रहा है। कंपनी ने एक बयान में कहा, 'हमें आयकर दल के हमारे कार्यालय आने और कुछ कर्मचारियों से साथ पूछताछ के बारे में बताया गया है। हुवावे को भरोसा है कि भारत में हमारा संचालन सभी कानूनों और विनियमों के अनुरूप है। हम अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी

टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ जांच

चीन की टेलिकॉम कंपनियों पर पिछले कुछ वर्षों के दौरान नियामकीय फाइलिंग और दूसरी तरह की रिपोर्टिंग में अनियमितता बरतने का आरोप है। देश के

मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा है। इनमें श्याओमी, ओप्पो और वीचो शामिल हैं। भारत में ये कंपनियों दोनों हाथों से कमा रही हैं लेकिन एक भी पैसे का टैक्स नहीं देती है। सरकार ने विस्तृत जांच शुरू की थी। यह जांच कई एजेंसियों कर रही है।

चीनी कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी इनकम के बारे में जानकारी छिपाई, टैक्स से बचने के लिए प्रॉफिट की जानकारी नहीं दी और भारतीय बाजार में धरेलू इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए अपने दबदबे का इस्तेमाल किया। साथ ही चीनी कंपनियों पर कंपोनेंट्स लेने और प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रिब्यूशन में पारदर्शिता नहीं बरतने का भी आरोप है।

खाद्य वस्तुओं के दाम ने बढ़ाई चुनौतियां

नई दिल्ली। एजेंसी

खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के बावजूद जनवरी, 2022 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति घटकर 12.96 प्रतिशत पर आ गई। दिसंबर, 2021 में थोक मुद्रास्फीति 13.56 प्रतिशत और जनवरी, 2021 में 2.51 प्रतिशत पर थी। थोक मुद्रास्फीति अप्रैल, 2021 से लगातार दसवें माह 10 प्रतिशत से ऊंची बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी, 2022 में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति बढ़कर 10.33 प्रतिशत पर पहुंच गई। दिसंबर, 2021 में यह 9.56 प्रतिशत थी। इसी तरह समीक्षाधीन महीने में सब्जियों की मूल्यवृद्धि 34.85 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पिछले महीने 31.56 प्रतिशत थी। दालों, अनाज और धान की मद्रास्फीति माह-दर-माह आधार पर बढ़ी। अंडा, मांस और मछली की मुद्रास्फीति जनवरी में 9.85 प्रतिशत रही। दूसरी ओर आलू के दाम माह के दौरान 14.45 प्रतिशत और प्याज के

15.98 प्रतिशत कम हुए। विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 9.42 प्रतिशत पर आ गई। दिसंबर, 2021 में यह 10.62 प्रतिशत थी। जनवरी में ईंधन और ऊर्जा खंड में मुद्रास्फीति 32.27 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले महीने 32.30 प्रतिशत थी।

कर्ज सस्ता करने से रोक रही महंगाई

रिजर्व बैंक इस माह की शुरुआत में मौद्रिक नीति की समीक्षा में लगातार 10वीं बार मीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने



खुदरा महंगाई और खाद्य महंगाई के मदेनजर कई बार दरों में बदलाव से परहेज किया है। आरबीआई कई बार सरकार से कह चुका है कि महंगाई से

मुकाबला करने के लिए चौतरफा कोशिश करनी होगी। इसके लिए आपूर्ति पक्ष समेत अन्य उपायों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

खाद्य महंगाई घटाने के लिए उठाए कई कदम

सरकार ने महंगाई और खासकर खाने-पीने के वस्तुओं की महंगाई को कम करने के लिए पिछले एक साल में कई तरह के प्रयास किए हैं। इसके लिए खाद्य तेल के आयात शुल्क को कई बार घटाया गया। इसके अलावा कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई की गई। इसके बावजूद खाद्य महंगाई ऊंची बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेमौसम बारिश की वजह से भी उत्पादन और आपूर्ति पर असर पड़ा है जिससे खाद्यान महंगे हुए हैं।

मुद्रास्फीति का रुख अब नीचे की ओर : शक्तिकांत दासभारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का मानना है कि मुद्रास्फीति का रुख अब नीचे की ओर है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक मूल्यवृद्धि और आर्थिक वृद्धि के बीच एक उचित संतुलन कायम करने का काम जारी रखेगा। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की बैठक के बाद दास ने यह बात कही। इस बैठक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया।

रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति का अनुमान 'मजबूत'

दास ने कहा कि रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति का अनुमान 'मजबूत' है, लेकिन इसका रुझान नीचे की ओर है। हालांकि, इसके साथ वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों का जोखिम जुड़ा है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक कोई राय बानाने से पहले कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के एक निश्चित दायरे पर गैर करता है। उन्होंने कहा कि मूल्य स्थिरता निश्चित रूप से हमारे दिमाग में है। इसका आशय मुद्रास्फीति के लक्ष्य पर टिके रहने से है। रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जानता है और साथ ही उसे वृद्धि के उद्देश्य की भी जानकारी है। दास ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर से मुद्रास्फीति का रुख नीचे की ओर है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से सांख्यकीय कारणों की वजह से विशेषरूप से तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति ऊंची दिख रही है। इसी आधार प्रभाव का असर अगले कुछ माह के दौरान भी दिखेगा। रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह कहा था कि सकल मुद्रास्फीति (हेलाइन इनफ्लेशन) चालू वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में ऊपर जाएगी, लेकिन यह संतोषजनक दायरे में बनी रहेगी। इसके बाद 2022-23 की दूसरी छमाही में यह घटकर लक्ष्य के पास आएगी।

रूस द्वारा यूक्रेन पर संभावित आक्रमण का बढ़ता डर भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम तेल की कीमतों को 120 डॉलर तक

एजेंसी

विश्लेषकों का तेल पर तेजी से रुख हो रहा है, कुछ की भविष्यवाणी की कीमतों में 120 तक पहुंचने का अनुमान है। रूस यूरोपीय संघ का एक प्रमुख निर्यातक है, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका को कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक भी है। वहाँ पहले से ही बहुत सारे तेल बैल हैं, लेकिन एक और उनके साथ जुड़ गया है। रणनीतिक डेविड रोश ने कहा कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण की स्थिति में इस सप्ताह तेल 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। यूक्रेन की स्थिति अब हफ्तों से सुर्खियों में है, और कोई यह तर्क दे सकता है कि अगर रूस आक्रमण करना चाहता था, तो उसने पहले ही ऐसा कर लिया होता, इस तर्क का समर्थन करते हुए कि रूस को इस तरह के कदम से बहुत कुछ हासिल करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर, यह एक तथ्य है कि यूक्रेन के साथ सीमा के पास रूसी सैनिक

और सैन्य उपकरण हैं, और यह स्वाभाविक रूप से न केवल यूक्रेन बल्कि पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को परेशान कर रहा है, प्रतिवाद के साथ कि मास्को अपनी बोली लगा रहा है हमला करने से पहले का समय। कुल मिलाकर, यूक्रेन की स्थिति ने रूसी प्राकृतिक गैस पर यूरोप की निर्भरता और पिछले कुछ हफ्तों में कटऑफ के मामले में इस आपूर्ति के विकल्प को सुरक्षित करने के लिए उसके हताश प्रयासों को उजागर किया है। लेकिन, किसी भी प्रमुख भू-राजनीतिक घटना की तरह, यूक्रेन में वृद्धि भी तेल की कीमतों को प्रभावित करेगी।

'मुझे लगता है कि अगर यूक्रेन पर आक्रमण हुआ था और ऐसे प्रतिबंध थे जो रूस की विदेशी मुद्रा तंत्र, संदेश प्रणाली आदि तक पहुंच को बाधित करते थे, या जो उन्हें अपनी वस्तुओं, या तो तेल या गैस या कोयले के नियात से रोकते थे, मुझे लगता है उस समय आप निश्चित रूप से तेल की कीमतें 120 डॉलर बैरल पर देखेंगे,'

यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए मंजूरी के पतन का



मुद्रा एक बड़ी संभावित समस्या के रूप में सामने आया है: रूस यूरोपीय संघ का एक प्रमुख निर्यातक है, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक भी है, न कि उन सभी बड़े यूरोपीय और अमेरिकी व्यवसायों का उल्लेख करें जिनके पास रूसी परिचालन है।

फिर भी जबकि एक आक्रमण एक संभावित विकास बना हुआ है, तेल क्षेत्र में पर्याप्त वास्तविक विकास प्रतीत होता है जो कीमतों को 100 प्रति बैरल से ऊपर देख सकता है। आपूर्ति तंग बनी हुई है, और व्यापारी इसके बारे में चिंतित रहते हैं, भले ही अमेरिकी उत्पादन के बारे में नवीनतम पूर्वानुमान एक उत्पादित नोट पर हमला करते हैं।

उदाहरण के लिए, ऊर्जा सूचना प्रशासन ने हाल ही में अनुमान लगाया था कि अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन इस साल बढ़कर 12 मिलियन बीपीडी और 2023 में 12.6 मिलियन बीपीडी-एक रिकॉर्ड-उच्च होना चाहिए। पिछले साल के अंत में, एचआईएस मार्किट के डैनियल येरगिन ने अमेरिकी तेल का अनुमान लगाया

था। उत्पादन इस साल एक दिन में 900,000 बीपीडी जोड़ सकता है। संदर्भ के लिए, ईआईए की नवीनतम साप्ताहिक पेट्रोलियम रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह उत्पादन औसतन 11.6 मिलियन बीपीडी था।

अन्य गैर-ओपेक उत्पादकों को भी इस वर्ष अधिक उत्पादन देखने को मिल सकता है, जिसमें ब्राजील और कनाडा शामिल हैं, लेकिन ओपेक की स्थिति स्वयं थोड़ी अधिक जटिल है। कार्टेल के अधिकांश सदस्यों को उत्पादन बढ़ाने में उतनी ही परेशानी हो रही है जितनी उनके नए कोटा की मांग है। यह तेजी से तेल की कीमतों के पूर्वानुमान का मुख्य कारण बन गया है, वास्तव में, क्योंकि यह कमोडिटी के लिए आईईए की अपेक्षा मजबूत-मजबूत मांग के साथ संयुक्त है।

केवल कुछ मुट्ठी भर ओपेक सदस्य ही कुल उत्पादन में अधिक बैरल जोड़ सकते हैं। अभी के लिए, वे कुछ चुनिंदा लोग ऐसा करने के लिए अनिच्छा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उपभोग करने वाले देशों का दबाव बढ़ता रहेगा, हालांकि, बाद में बदल सकता है। वर्तमान आपूर्ति के संदर्भ में, वैश्विक वस्तु-ईंधन वाले आर्थिक संकट को पैदा किए बिना यूक्रेन की स्थिति को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है।

मजबूत और लोचदार, फिर भी सड़ने योग्य प्रोटीन आधारित बायोप्लास्टिक्स



हर साल महासागरों में 80 लाख टन से अधिक प्लास्टिक खत्म हो जाता है-पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा। नायोटिंग्डो डे बल बायोप्लास्टिक एक विकल्प प्रदान कर सकता है। एंजवेन्टे केमी पत्रिका में, एक शोध दल ने अब प्रोटीन-आधारित प्लास्टिक के उत्पादन के लिए एक नई विधि पेश की है जो आसानी से संसाधित, बायोडिग्रेडेबल और बायोकंपैटिबल होने के साथ-साथ अनुकूल यांत्रिक गुणों के साथ है।

चाहे पैकेजिंग हो या खिलौने, मल्टी फिल्म या कार, पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित प्लास्टिक सर्वव्यापी हैं-मांग बढ़ रही है, और कचरे के ढेर भी हैं। स्टार्च जैसी प्राकृतिक सामग्री पर आधारित बायोप्लास्टिक, या पॉलीलैकिटिक एसिड जैसे सिंथेटिक बायोमैट्रियल्स ने ज्यादातर मामलों में अपर्याप्त स्थायित्व, जैव-अनुकूलता और/या बायोडिग्रेडेबिलिटी का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, उन्हें अक्सर जटिल, ऊर्जा-गहन प्रसंस्करण

है जिन्हें जरूरत के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दो लाइसेन्स युक्त प्रोटीन विकसित किए और उन्हें जीवाणु संस्कृतियों में उत्पादित किया: 'ईएलपी' संयोजी ऊतक प्रोटीन इलास्टिन वेट समान एक टीम ने अब ऐसे गुणों के साथ तह नहीं है, जो कठोरता और लोच

की ओर जाता है। 'पींक' में शीट संरचना के साथ स्क्वीड प्रोटीन के थिंग्लस क्रिस्टलीय खंड होते हैं। ईएलपी (या एसआरटी) अपने लाइसेन्स अमीनो साइड-ग्रुप्स के माध्यम से पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल (पीईजी) व्युत्पन्न के साथ क्रॉसलिंक किया गया है। (पीईजी

का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स में, अन्य चीजों के साथ किया जाता है।) यदि पानी में क्रॉसलिंकिंग होती है, तो सामग्री को केवल एक सांचे में सुखाया जा सकता है। परिणाम एक कठिन, पारदर्शी, विलायक प्रतिरोधी बायोप्लास्टिक है। खुट्टी के अनुपात को बदलकर इसके यांत्रिक गुणों को बदला जा सकता है। यह किसी भी वांछित आकार में कर्मरे के तापमान पर उच्च यांत्रिक शार्ट्ट वेट साथ बायोप्लास्टिक के उत्पादन की अनुमति देता है, और बिना जहरीले रसायनों या जटिल प्रसंस्करण चरणों जैसे द्रवीकरण, एक्स्ट्रॉजन, या झटका मोलिंग के बिना। उनका ब्रेकिंग स्ट्रेस कई व्यावसायिक प्लास्टिक से अधिक है। एक समस्या बची है कि वे पानी में सूज जाते हैं।

यदि ईएलपी को पानी/गिलसरॉल के घोल में क्रॉसलिंक किया जाता है, तो सामग्री जैल को नरम, लोचदार बायोप्लास्टिक में बदल देती है। टीम ने बायोफाइबर का उत्पादन करने के लिए गीली कताई का भी मुकाबले उच्च सूचना घनत्व की अनुमति देगा।

मजबूत प्रदर्शन की गति के साथ ग्रेसिम ने बनाये रखी निरंतरता

1 जनवरी 2022 पर, स्टैंडअलोन व्यवसाय में फर्टिलाइजर्स व्यवसाय के विनिवेश की समाप्ति पर सकल ऋण शून्य पर रह.

विभिन्न विस्तार प्रोजेक्ट्स की सफलतापूर्वक शुरुआत विलायत ब्राउनफील्ड का 220 केटीपीए क्षमता का वीएसएफ प्रोजेक्ट 2 चरणों में शुरू, इसमें 110 केटीपीए नवम्बर 21 में और बचा हुआ 110 केटीपीए फरवरी 22 में प्रारम्भ

कास्टिक सोडा: 117 केटीपीए (बी बी पुरम, आंध्रप्रदेश फेज़-1: 26 केटीपीए तथा रेहला, झारखंड 91 केटीपीए) (दिसंबर 21)

2040 तक सम्पूर्ण वीएसएफ व्यवसाय में कुल कॉर्बन उत्सर्जन शून्य करने की ओर अग्रसर कंसोलिडेटेड राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़कर 24, 402 करोड़ तथा कंसोलिडेटेड पीएटी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 26 प्रतिशत बढ़कर 1,746 करोड़ पर पहुंचा

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड राजस्व 16 प्रतिशत बढ़कर रूपये 24,402 करोड़ पर पहुंचा, ईबीआईटीडीए रूपये 4,107 करोड़ पर रहा और पीएटी 26 प्रतिशत बढ़कर रूपये 1,746 करोड़ पर पहुंचा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही पर स्टैंडअलोन राजस्व 56 प्रतिशत की ऊँची छलांग मारकर रूपये 5,785 करोड़ पर पहुंचा, ईबीआईटीडीए 36 प्रतिशत बढ़कर रूपये 963 करोड़ रूपये पर पहुंचा और पीएटी 46 प्रतिशत बढ़कर बंद किये गये संचालनों (फर्टिलाइजर व्यवसाय) से प्राप्त राजस्व तथा ईबीआईटीडीए वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही के लिए क्रमशः रूपये 974 करोड़ तथा रूपये 53 करोड़ रहा (वित्तीय वर्ष 21 की तीसरी तिमाही: रूपये 598 करोड़ तथा रूपये 57 करोड़)

विस्कोज़ बिजनेस

यूप्स और यूरोप में टैक्सटाइल उत्पादों में वैश्विक मांग में वृद्धि होने से वीएसएफ के लिए सकारात्मक मांग का माहौल बना. वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में थोड़ी सी मंदी के बाद जनवरी

22 में चीनी फाइबर और यार्न मैन्युफेक्चरर ऑपरेटिंग रेट्स (ओआर) में तेज वृद्धि दर्ज की. जनवरी 22 में वीएसएफ के लिए ओआर सुधरकर 12 महीनों के ऊँचे आंकड़े 83 प्रतिशत पर पहुंचा और यार्न के लिए भी ओआर सुधरकर 55 प्रतिशत पर आया. वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में वीएसएफ के दाम पिछली तिमाही की तुलना में औसतन ऊँचे रहे.

हालांकि दिसंबर 21 के अंत तक कोविड-19 के कारण वसूली ने नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया था. वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद, भारत में टैक्सटाइल उत्पादों के लिए मजबूत मांग ने वीएसएफ के संचालन को मजबूती दी. वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही के लिए वीएसएफ की बिक्री मात्रा विलायत में ब्राउनफील्ड विस्तार (300 टीटीडी) के शुरू होने से और आगे बढ़ी. कुल मिश्रित बिक्री में वैल्यू एडेंट उत्पादों का हिस्सा बढ़कर 29 प्रतिशत पर पहुंचा। लागत के दबाव के बावजूद वीएसएफ व्यवसाय ने वसूली में सुधार और मजबूत मांग के चलते क्रमबद्धता के आधार पर सशक्त संचालन और वित्त संबंधी प्रदर्शन दर्ज किया।

कैपेक्स (पूँजीगत खर्च) योजना

यह तिमाही वीएसएफ और कैमिकल दोनों ही व्यवसाय में जारी विभिन्न कैपेक्स प्रोजेक्ट्स की साक्षी बनी है. विलायत में वीएसएफ ब्राउनफील्ड विस्तार की 300 टीटीडी लाइन (कुल 600 टीटीडी में से) का काम नवंबर-21 से प्रारम्भ हो चुका है और पूरी क्षमता से संचालित हो रहा है. जबकि शेष 300 टीटीडी की दूसरी लाइन 12 फरवरी 2022 से सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है. कलोर-अल्कली व्यवसाय में 26 केटीपीए क्षमता का बी बी पुरम (फेज-1) प्लांट दिसंबर 21 सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है जबकि शेष बचा हुआ (47 केटीपीए) वित्तीय वर्ष 23 की पहली तिमाही तक शुरू

अपने आप में सराहनीय है और यह चालू वित्त वर्ष के लिए 400 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पार करने के लिए नियांतकों के बीच नए उत्साह का संचार भी करता है। डॉ. शक्तिवेल ने नियांतकों के प्रयासों तथा कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जिनकी नियांतकों के प्रति की गई अपील ने नियांतक समुदाय को ऐसा असाधारण प्रदर्शन करने के लिए और अधिक जोश से भर दिया। डॉ. शक्तिवेल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम तथा गतिशील नेतृत्व में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों तथा केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग एवं कपड़ा मंत्री द्वारा इस कठिन समय में नियांतकों पर

QUARTERLY FINANCIAL RESULTS						Cr.
Standalone			Consolidated			
Q3FY22	Q3FY21	% Change (Y-o-Y)	Revenue	Q3FY22	Q3FY21	% Change (Y-o-Y)
5,785	3,697	56%	Revenue	24,402	21,000	16%
963	708	36%	EBITDA	4,107	4,476	-8%
522	358	46%	PAT	1,746	1,389	26%

कैमिकल बिजनेस

वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में, लगातार ऊँची तिमाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैमिकल सोडा के दामों ने ऊँची बढ़त जारी रखी है. घरेलू कैमिकल सोडा के दामों ने भी कैमिकल के दाम के मामले में अंतर्राष्ट्रीय चलन को प्रतिविम्बित किया है, घरेलू मांग की स्थितियों ने भी दाम को बढ़ाने में सहयोग किया। वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में कैमिकल सोडा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन (क्षमता का उपयोग) क्रमवर 7 प्रतिशत बढ़ते हुए 9.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है. कलोर अल्कली व्यवसाय सम्पूर्ण पावर मिक्स में ग्रीन पावर की हिस्सेदारी बढ़ाने के रास्ते पर है और यह 3.4 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 22 के नीचे महीने) से 10 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 23) की ओर बढ़ रहा है. यह आगे स्टेनबिलिटी के प्रदर्शन को बढ़ाने के साथ ही दामों में प्रतियोगितामुक्ता की ओर भी कदम बढ़ाएगा। एडवांस मटेरियल व्यवसाय ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में संचालन और वित्तीय प्रदर्शन दोनों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया, जिसके पीछे विंड पावर सैगमेंट में सशक्त मांग अ और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स कारण बना।

पेंट व्यवसाय

पेंट मैन्युफेक्चरिंग के क्षेत्र में कम्पनी ने अपनी पांच में से दो प्लांट साइट्स के लिए एन्यावरमेंटल क्लियरेंस हासिल कर लिया है. यह सम्पूर्ण भारत में अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाने की योजना का एक हिस्सा है।

यह तिमाही वीएसएफ और कैमिकल दोनों ही व्यवसाय में जारी विभिन्न कैपेक्स प्रोजेक्ट्स की साक्षी बनी है. विलायत में वीएसएफ ब्राउनफील्ड विस्तार की 300 टीटीडी लाइन (कुल 600 टीटीडी में से) का काम नवंबर-21 से प्रारम्भ हो चुका है और पूरी क्षमता से संचालित हो रहा है. जबकि शेष 300 टीटीडी की दूसरी लाइन 12 फरवरी 2022 से सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है. कलोर-अल्कली व्यवसाय में 26 केटीपीए क्षमता का बी बी पुरम (फेज-1) प्लांट दिसंबर 21 सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है जबकि शेष बचा हुआ (47 केटीपीए) वित्तीय वर्ष 23 की पहली तिमाही तक शुरू

होने की संभावना है. 9.1 केटीपीए के रेहला प्लांट और विलायत (गुजरात) में 55 केटीपीए क्षमता का क्लोरोरोमीथेन प्लांट भी वित्तीय वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में शुरू हो गया था।

स्टेनबिलिटी/निरंतरता

कम्पनी के वीएसएफ व्यवसाय ने वर्ष 2040 तक अपने सभी संचालनों में नेट ज़ेरो कार्बन उत्सर्जन पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है. कम्पनी ने पहली बार 2021 में सीडीपी (कार्बन डिस्कोलोजर प्रोजेक्ट) में प्रतिभागिता की थी और मैनेजमेंट बैंड स्कोर-बी हासिल किया। खरच की वीएसएफ यूनिट एनवायरमेंट मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए सीआईआई-आईटीसी स्टेनबिलिटी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। ग्रेसिम ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से 'इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग' के लिए गोल्ड शील्ड अवार्ड तथा 'एसीलेंस इन फाइनेशियल रिपोर्टिंग' पुरस्कार भी प्राप्त किया।

सीमेंट स्लिसडियरी- अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अल्ट्रा टेक का समेकित राजस्व 6 प्रतिशत बढ़कर 12,985 करोड़ रुपये। कम्पनी ने रुपये 2,490 करोड़ का ईबीआईटीडीए दर्ज किया और सेल्स वॉल्यूम 123.13 एमटीपीए रही. इनपुट कॉस्ट में बढ़ोत्तरी का प्रभाव सम्पूर्ण बोर्ड पर देखा गया, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एनर्जी कॉस्ट बढ़कर 39 प्रतिशत, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़कर 7 प्रतिशत और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़कर 29 प्रतिशत पर पहुंचा। लागत के दबाव के बावजूद वीएसएफ व्यवसाय ने वसूली में सुधार और मजबूत मांग के चलते क्रमबद्धता के आधार पर सशक्त संचालन और वित्त संबंधी प्रदर्शन दर्ज किया।

News यू केन USE

भारत केंद्रित ऑफशोर कोषों, ईटीएफ से दिसंबर तिमाही में 43.5 करोड़ डॉलर की निकासी : रिपोर्ट नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत केंद्रित ऑफशोर कोषों और एक्सेंजेंट्रेड कोषों (ईटीएफ) से दिसंबर, 2021 में समाप्त तिमाही में 43.5 करोड़ डॉलर की निकासी हुई। मार्निंगस्टार की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस तरह यह लगातार 15वीं तिमाही है जबकि भारत केंद्रित ऑफशोर कोषों और ईटीएफ से निकासी हुई है। इससे पहले सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही में इन कोषों से निवेशकों ने 9.5 करोड़ डॉलर निकाले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान वैश्विक और घरेलू मूर्चे पर चिंताएं बढ़ने और अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 145 अंक टूटा, निपटी में भी गिरावट

मुंबई। एजेंसी

भारी उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 145 अंक से अधिक टूटकर 58,000 अंक के स्तर से नीचे आ गया। रूस-यूक्रेन के बीच तनाव दूर होने के संकेत के साथ वैश्विक बाजारों में तेजी के बाजू घेरेलू बाजारों में गिरावट रही। तीस शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक-सेंसेक्स में कारोबार के दौरान 800 अंकों का उतार-चढ़ाव आया। अंत में यह 145.37 अंक यानी 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,996.68 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निपटी लाभ-हानि के बीच घूमते हुए अंत में 30.25 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,322.20 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में एनटीपीसी, एसबीआई, अल्ट्राटेक

बैंक, टाटा स्टील, बजाज फिनर्स और बजाज फाइनेंस प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। इनमें 1.63 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

दूसरी तरफ, भारती एयरटेल का शेयर 1.41 प्रतिशत बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहा। इसके अलावा एचडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉ. रेडीज, कोटक बैंक और नेस्ले इंडिया में भी प्रमुख रूप से तेजी रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 नीचे आए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, “रूस-यूक्रेन संकट पर निवेशकों की नजर होगी। इसके अलावा साप्ताहिक आधार पर सौदों के निपटान को देखते हुए बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। हमारा निवेशकों के लिए चीजें साफ होने तक सर्तक रुख का सुझाव बरकरार है।” एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निककी, चीन का शंघाई कंपोजिट, हांगकांग का ब्रेंट वायदा 0.19 प्रतिशत गिरकर

उन्होंने कहा, “मुद्रास्फीति को लेकर वैश्विक स्तर पर दबाव बना



हुआ है। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर 5.5 प्रतिशत पहुंच गयी, जो 30 साल का उच्चस्तर है। इससे बैंक ऑफ इंग्लैण्ड पर नीतिगत दर में एक और वृद्धि का दबाव बना है।” रेलिंगर ब्रोकिंग लि. के उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा कि बाजार इस समय वैश्विक धुन पर झूम रहा है और यह प्रवृत्ति बनी रह सकती है। उन्होंने कहा, “अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का व्योरा तथा रूस-यूक्रेन संकट पर निवेशकों की नजर होगी। इसके अलावा साप्ताहिक आधार पर सौदों के निपटान को देखते हुए बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। हमारा निवेशकों के लिए चीजें साफ होने तक सर्तक रुख का सुझाव बरकरार है।” एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निककी, चीन का शंघाई कंपोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का

93.06 डॉलर प्रति बैरल पर आ आंकड़ों के अनुसार, विदेशी रूपए के प्रमुख बाजारों में भी दोपहर कारोबार में तेजी का रुख था। इस बीच, वैश्विक कच्चा तेल मानक ब्रेंट वायदा 0.19 प्रतिशत गिरकर

संस्थागत निवेशक मंगलवार को पूंजी बाजार में शुद्ध बिकाल रहे और उन्होंने 2,298.76 करोड़ रूपए गई। शेयर बाजारों के अस्थायी मूल्य के शेयर बेचे।

डिजिटल रुपया और UPI पेमेंट में क्या है फर्क कैसे होगा लेनदेन- जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में बहुत जल्द डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक अगले वित्त वर्ष में डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी। खबर है कि RBI इस डिजिटल करेंसी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करेगा। नई करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी।

लङ्घ पेमेंट से कैसे अलग होगा डिजिटल रुपया ?

अब जब देश के पास अपना डिजिटल रुपया होगा तो लोग डिजिटल करेंसी से ही खरीदारी कर सकेंगे, हर वो जरूरी काम जिसके लिए लोग अभी यूपीआई पेमेंट करते हैं उसकी जगह डिजिटल करेंसी से भी लेन देन कर सकेंगे। हालांकि, इसका इस्तेमाल कहां होगा यह अभी किल्यर नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह काम कैसे करेगा और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान से कैसे अलग



होगा?

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर और पेमेंट्स ट्रांसफर्मेशन लीडर, मिहिर गांधी बताते हैं, ‘‘डिजिटल रुपया अपने आप में अंडरलाइंग भुगतान मोड होगा जिसका उपयोग करेंसी/कैश के बदले डिजिटल भुगतान के लिए किया जा सकेगा। लङ्घ और छश्शे आदि जैसे भुगतान फंड ट्रांसफर करने के लिए अंतर्निहित मुद्रा/नकदी का उपयोग करते हैं। इस मामले में, यह उम्मीद की जाती है कि डिजिटल रुपया से भुगतान सहज लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है। वर्तमान में, लङ्घ भुगतान मौजूदा मुद्रा नोटों के

डिजिटल समक्ष का उपयोग करके किया जाता है। इसका मतलब है कि लङ्घ के जरिए ट्रांसफर किया गया हर रुपया फिजिकल करेंसी से चलता है।

हर बैंक का एक अलग UPI हैंडलर होता है

डिजिटल रुपया आपके सामान्य रुपये से अलग नहीं है। इसका उपयोग एनईएफटी, यूपीआई जैसे सामान्य लेनदेन के लिए किया जा सकता है। प्रोएसेट्ज़ एक्सचेंज के संस्थापक और निवेशक मनोज डालमिया ने कहा कि यूपीआई के मामले में डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा संचालित किया

जाएगा, न कि बैंक मध्यस्थों द्वारा, जहां प्रत्येक बैंक का एक अलग यूपीआई हैंडलर है। नॉनब्लॉक्स ब्लॉकचेन स्टूडियो के संस्थापक और निवेशक विंशु गुप्ता ने कहा कि यूपीआई भुगतान वर्तमान में आरबीआई के साथ लेनदेन करने वाले बैंकों के निपटान पर निर्भर करता है, डिजिटल रुपे सीधे आरबीआई से लेनदेन करेगा, इसलिए इसे तुरंत सुलझा लिया जाएगा। बता दें कि UPI ट्रांजेक्शन सीधे बैंक से बैंक में होता है, यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एडेंट और आइडेंटी का इस्तेमाल करता है।

जानिए कैसे होगा ट्रांजेक्शन

डिजिटल रुपये वास्तव में ब्लॉकचेन सहित अन्य टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंसी होगी। यह करेंसी की तरह ही काम करेगा। साथ ही CBDC को नोट के साथ बदला भी जा सकेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखाई देगी। RBI की रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि CBDC से आप कैश के मुकाबले आसानी से और सुरक्षित तरीके से कहीं पर भी खरीदारी कर सकेंगे।

बड़े देशों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की गति होगी सबसे तेज

नई दिल्ली। एजेंसी

बड़े देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से विकास करेगी। ऐसा केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2022-23 में की गई विभिन्न पहलों की बजह से होगा। इसका उल्लेख केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में किया गया है।

वृद्धि के मुख्य वाहक ये

मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े देशों में सबसे तेज गति से वृद्धि दर्ज करेगी। समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘पीएलआई योजनाओं और बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के चलते विनियोग और निर्माण क्षेत्र वृद्धि के मुख्य वाहक होंगे।’’

कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के जरिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य और आय हस्तांतरण से कृषि क्षेत्र में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अभी तक एकमात्र बड़ा और प्रमुख देश है, आईएमएफ ने जिसका वृद्धि अनुमान 2022-23 के लिए बढ़ाया है। गैरतलब है कि आईएमएफ ने वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक वृद्धि अनुमान को घटा दिया है।

2020-21 में घटी थी दर

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘भारत के लोगों के लंबीलेपन और उसकी नीति निर्माण की दूरदृशीता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के 2022-23 में दुनिया के बड़े देशों के बीच सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान है, जबकि यह 2020-21 में 6.6 प्रतिशत घटी थी।’’ रिपोर्ट में कहा गया है कि आम बजट 2022-23 ने पिछले बजट में तय दिशा को मजबूत किया।